Result Mitra Daily Magazine

सावरेन गोल्ड बांड (SGB)

➢ चर्चा में क्यों ?

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) योजना के वित्त पोषण की उच्च लागत के कारण सावरेन गोल्ड बांड (SGB) योजना को बंद करने पर विचार कर रही है।
- सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा सावरेन गोल्ड बांड (SGB) योजना सोने (GOLD) में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जारी की गई थी, लेकिन 2024–25 की केंद्रीय बजट में सोने पर आयात शुल्क में कटौती के हालिया घोषणा के कारण सरकार इस योजना को बंद करने पर विचार कर रही है।
- वित्तीय वर्ष 2024–25 की केंद्रीय बजट में सोने पर आयात शुल्क की कटौती के कारण सोने की मांग बढ़ने में मदद मिली है।
- इस वर्ष की शुरुआत से ही सरकार द्वारा सावरेन गोल्ड बॉन्ड के माध्यम से राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण की उच्च लागत को देखते हुए इस योजना को बंद करने पर विचार कर रही है।

➢ सावरेन गोल्ड बॉन्ड योजना क्या है ?

- सावरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई ऋण प्रतिभूतियां हैं, जिनमें प्रत्येक इकाई एक ग्राम सोने को दर्शाती है।

- भारत सरकार अपने राजकोषीय घाटे को दिनांकित प्रतिभूतियों, राष्ट्रीय लघु बचत निधि (NSSF), भविष्य निधि और सावरण गोल्ड बांड (SGB) सहित विभिन्न उपकरणों के माध्यम से वित्त पोषित करती है।
- सावरेन गोल्ड बांड द्वितीयक बाजार में व्यापार का लचीलापन प्रदान करते हैं, जिससे निवेशकों को पूंजीगत लाभ अर्जित करने का अवसर मिलता है।
- सावरेन गोल्ड बॉन्ड पर 2.5 प्रतिशत का निश्चित ब्याज मिलता है, जिससे अनुमानित आय प्रवाह सुनिश्चित होता है।
- सावरेन गोल्ड बॉन्ड एक सरकारी प्रतिभूतियां हैं, जो लोगों को भौतिक रूप से सोना रखने का विकल्प प्रदान करती है।
- इस गोल्ड बांड में निवेशकों को निर्गम मूल्य का भुगतान नगद में किया जाता है और इसकी अवधि पूरा होने पर भी बांड को नगद में ही भुनाया जाता है।
- इस योजना में जोखिम और भंडारण की लागत बहुत ही कम होती है, जिसमें निवेशकों को परिपक्वता के समय सोने के बाजार मूल्य और आवधिक ब्याज का आश्वासन दिया जाता है।
- इस SGB की अवधि 8 वर्ष है, लेकिन इसे 5 वर्ष की अवधि पूरा होने पर भुनाया जाता है।

➢ SGB योजना कब शुरू की गई थी ?

- केंद्र सरकार द्वारा नवंबर 2015 में गोल्ड मुद्रीकरण योजना के तहत सावरेन गोल्ड बांड (SGB) की शुरुआत की गई थी।
- इस योजना के तहत केंद्र सरकार के परामर्श से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किश्तों में सोने में निवेश शुरू किया गया था।
- समय–समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस योजना के लिए नियम एवं शर्तों को अधिसूचित किया जाता है।
- ज्वेलरी के रूप में इस योजना के तहत निवेश में मेकिंग चार्ज और शुल्क जैसे मुद्दों से मुक्त होता है।
- इस योजना के तहत सोने की न्यूनतम स्वीकार्य सीमा 1 ग्राम है।
- इस योजना के तहत सोने की अधिकतम निवेश की सीमा एकल व्यक्ति के लिए 4 किलोग्राम, हिंदू अविभाजित परिवार के लिए 4 kg और ट्रस्टो के लिए 20 किलोग्राम है।
- उपरोक्त अधिकतम सीमा प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए लागू है।

➢ सावरेन गोल्ड को लेकर क्या चिंताएं हैं ?

- सरकार का आंतरिक विचार यह है कि सावरेन गोल्ड बांड (SGB) के माध्यम से राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण की लागत काफी अधिक है, जो योजना से निवेशकों को होने वाले लाभ के अनुरूप नहीं है।
- SGB योजना की शुरुआत में 1 वर्ष में 10 किश्तें होती थी, जो बाद में घटकर चार फिर अंत में दो किश्त हो गई।
- इस योजना के तहत राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण की लागत और भौतिक सोने के संग्रह से होने वाले लाभ अलग-अलग है।
- इस वर्ष जुलाई में केंद्रीय बजट के दौरान सोने पर आयात शुल्क को 15% से घटाकर 6% कर दिया गया, जो पिछले एक दशक में सबसे कम आयात शुल्क है।
- सोने पर आयात शुल्क में कटौती के कारण सोने की कीमतों में कमी आई, जिसके परिणाम स्वरुप सोने की मांग में भी वृद्धि दर्ज की गई।
- चूंकि SGB योजना एक सार्वजनिक क्षेत्र की योजना न होकर एक निवेश विकल्प है। इसलिए सरकार का मानना है कि योजना को जारी रखने में ज्यादा फायदा नहीं है।
- इस वर्ष 23 जुलाई को पेश बजट में सरकार द्वारा 1 फरवरी के अंतिम बजट में SGB योजना के तहत जारी राशि 29,638 करोड़ को घटाकर 18,500 करोड़ कर दिया गया।
- हालांकि चालू वित्त वर्ष में अब तक सरकार द्वारा कोई सावरेन गोल्ड बांड जारी नहीं किया गया है।
- जुलाई में पेश बजट में SGB के माध्यम से शुद्ध उधारी पहले के अनुमानित 26,138 करोड़ से घटाकर 15,000 करोड़ रुपए कर दी गई है।

➢ राजकोषीय घाटा क्या है ?

- राजकोषीय घाटा को सामान्य तौर पर सरकार की कुल आय (कुल करों और गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों सहित और उसके कुल व्यय के बीच के अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- राजकोषीय घाटा तब होता है जब सरकार का वह उसकी आय से अधिक हो जाता है।

➢ स्वर्ण भंडार :

- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2024 के अंत तक RBI के पास 854.73 मीट्रिक टन सोना था, जिसमें से 510.46 मीट्रिक टन सोना घरेलू स्तर का था।
- भारत की कुल विदेशी भंडार में सोने की हिस्सेदारी मार्च 2024 के अंत में 8.15% से बढ़कर सितंबर 2024 के अंत में लगभग 9.32 प्रतिशत हो गई।
- पिछले कुछ वर्षों में मुद्रास्फीति और सोने की कीमतों में तेजी देखी गई है।

- RBI द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार का एक घटक बनाए रखता है जिसमें विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों की हिस्सेदारी सबसे अधिक होती है।
- किसी भी देश का स्वर्ण भंडार उस देश के केंद्रीय बैंक को अपने विदेशी मुद्रा होल्डिंग्स में विविधता लाने में मदद करता है। साथ ही डी–डॉलरीकरण प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका के पास विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है, जो 8133.46 टन है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका का कुल स्वर्ण भंडार विश्व के दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान रखने वाले (स्वर्ण भंडार के मामले में) क्रमशः जर्मनी, इटली और फ्रांस के स्वर्ण भंडार के कुल योग के बराबर है।
- वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार स्वर्ण भंडार के मामले में पांचवें स्थान पर रूस, छठे स्थान पर चीन, सातवें स्थान पर जापान और आठवें स्थान पर भारत है।
- वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की स्थापना वर्ष 1987 में एक गैर–लाभकारी संगठन के रूप में विपणन, अनुसंधान और पैरवी के माध्यम से सोने के उपयोग और मांग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था।
- वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल लंदन (UK) में स्थित है।
- दुनिया भर में इसके अन्य कार्यालय न्यूयॉर्क, शंघाई, सिंगापुर, बीजिंग एवं मुंबई में स्थित है।
-